



Q.

Which of these Judicial case gave the historic judgement pronouncing, 'Airwaves are Free', 'Airwaves or Frequencies are a Public Property'? (West Bengal SET)

इनमें से किस न्यायिक मामले ने वह ऐतिहासिक निर्णय दिया जिसमें कहा गया, 'एयरवेव्स मुक्त हैं', 'एयरवेव्स या फ्रीक्वेंसी सार्वजनिक संपत्ति हैं'? (पश्चिम बंगाल SET)

A

Bennette Coleman & Co., V Union of India

B

Prabha Dutt v Union of India

C

Indian Express Newspaper V Union of India

D

Cricket Association of Bengal V Union of India



Explanation / व्याख्या

- In the Cricket Association of Bengal V Union of India case, the Supreme Court declared that airwaves are public property and must be regulated by a public authority to ensure their use is in the public interest.
- क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि एयरवेव्स सार्वजनिक संपत्ति हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका उपयोग सार्वजनिक हित में हो, उन्हें सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए।
- This judgment ended the government's monopoly over broadcasting.
- इस फैसले से प्रसारण पर सरकार का एकाधिकार समाप्त हो गया।





Which of these cases deal with Freedom of Speech and Expression?

निम्नलिखित में से कौन-से मामले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित हैं?

A

Justice Puttaswamy V Union of India
न्यायमूर्ति पुट्टस्वामी V भारत संघ

B

Romesh Thapar V State of Madras
रोमेश थापर V मद्रास राज्य

C

M.K. Stalin V Ananda Vikatan
एम.के. स्टालिन V आनंद विकटन

D

Kesavananda Bharati V State of Kerala
केशवानंद भारती V केरल राज्य



Answer / उत्तर: **Option B / विकल्प B**

Romesh Thapar V State of Madras
रोमेश थापर V मद्रास राज्य



Explanation / व्याख्या

- Romesh Thapar V State of Madras is a landmark case that deals with the freedom of speech and expression. रोमेश थापर V मद्रास राज्य एक महत्वपूर्ण मामला है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है।
- The Supreme Court held that Section 9(1-A) of the Madras Maintenance of Public Order Act, 1949, which imposed restrictions on the circulation of the journal "Cross Roads," was unconstitutional as it violated Article 19(1)(a).
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मद्रास लोक व्यवस्था (संरक्षण) अधिनियम, 1949 की धारा 9(1-A), जिसने पत्रिका "Cross Roads" के प्रसार पर प्रतिबंध लगाया था, असंवैधानिक है क्योंकि यह अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करती है।

Q

Which landmark case in Indian jurisprudence established the test for determining whether restriction on freedom of speech is valid or not? (Karnataka Set 2023)

भारतीय न्यायशास्त्र में किस ऐतिहासिक मामले ने यह निर्धारित करने की कसौटी स्थापित की कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध वैध है या नहीं? (कर्नाटक सेट 2023)



(A)

Kesavananda Bharati case

(B)

Maneka Gandhi case

(C)

Indira Gandhi case

(D)

Rammanohar Lohia case





Q.

The basic structure doctrine is an Indian Judicial principle that the Constitution of India has certain basic features that cannot be attend or destroyed through amendments by the parliament. In which specific case was this propounded? (MH SET 2023)

मूल संरचना सिद्धांत भारतीय न्यायिक सिद्धांत है जिसके अनुसार भारतीय संविधान की कुछ मूल विशेषताएँ ऐसी हैं जिन्हें संसद द्वारा संशोधन के माध्यम से बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता। इसे किस विशेष मामले में प्रतिपादित किया गया? (एमएच SET 2023)

A

Golak Nath versus State of Punjab

B

Sajjan Singh versus State of Rajasthan

C

Kesavananda Bharati versus State of Kerala

D

Indira Gandhi versus Raj Naraian



Explanation / व्याख्या

- It was a landmark decision of the Supreme Court of India that outlined the basic structure doctrine of the Indian Constitution.
- The case is also known as the Fundamental Rights Case.
- The basic structure doctrine was propounded in the Kesavananda Bharati versus State of Kerala case, where the Supreme Court held that the Parliament cannot amend the basic structure of the Constitution, ensuring certain fundamental features remain inviolable.

- यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय था जिसमें भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया।
- इस मामले को मौलिक अधिकार मामला भी कहा जाता है।
- मूल संरचना सिद्धांत केसवानंद भारती बनाम राज्य केरल मामले में प्रतिपादित किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती, जिससे कुछ मूलभूत विशेषताएँ अपरिवर्तनीय बनी रहें।





Which case is known for challenging the pre-censorship order imposed on a publication by the Chief Commissioner of Delhi?

कौन सा मामला दिल्ली के मुख्य आयुक्त द्वारा किसी प्रकाशन पर लगाए गए पूर्व-अनुमोदन आदेश को चुनौती देने के लिए जाना जाता है?



(A) Romesh Thappar vs State of Madras

(B) Brij Bhushan vs State of Delhi

(C) Sakal Papers vs Union of India

(D) Virendra vs State of Punjab

Explanation / व्याख्या

- Brij Bhushan vs State of Delhi is known for challenging the pre-censorship order on the magazine 'Organizer' by the Chief Commissioner of Delhi.
- Brij Bhushan vs State of Delhi को दिल्ली के मुख्य आयुक्त द्वारा पत्रिका 'Organizer' पर लगाए गए पूर्व-अनुमोदन आदेश को चुनौती देने के लिए जाना जाता है।
- The Supreme Court ruled that pre-censorship violated the freedom of the press.
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पूर्व-अनुमोदन आदेश प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।



Q. What did the Indian Express Newspapers vs. Union of India case challenge?

इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में क्या चुनौती दी गई?

A Imposition of customs duty and import duty on newsprint

- B** Pre-censorship orders on newspapers
- C** Ban on foreign publications
- D** Licensing of printing presses



Explanation / व्याख्या

- The Indian Express Newspapers vs. Union of India case challenged the imposition of customs duty and import duty on newsprint.

- इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में न्यूज़प्रिंट पर कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने को चुनौती दी गई।

- The Supreme Court held that while the state could regulate the economic aspects of newspapers, such regulations must not curtail the essential freedom of the press.

- सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि राज्य समाचारपत्रों के आर्थिक पहलुओं को विनियमित कर सकता है, लेकिन ऐसे विनियम प्रेस की आवश्यक स्वतंत्रता को सीमित नहीं करने चाहिए।





Sakal Papers (P) Ltd. and Others. vs. The Union of India (UOI), 1961, SC is a case related to (Sakal Papers (P) Ltd. and Others. vs. The Union of India (UOI), 1961, SC निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित मामला है?)

1

Sedition
देशद्रोह

2

Contempt of Court
न्यायालय की अवमानना

3

Press and Parliament Privileges Act
प्रेस एवं संसद विशेषाधिकार अधिनियम

4

Freedom of Press
प्रेस की स्वतंत्रता



Answer / उत्तर: Option 4 / विकल्प 4
Freedom of Press
प्रेस की स्वतंत्रता



Explanation / व्याख्या

- Sakal Papers (P) Ltd. v. The Union of India was a 1962 Constitution Bench case in which the Supreme Court ruled that the Newspaper (Price and Page) Act, 1956 and the Daily Newspapers (Price and Page) Order, 1960 were unconstitutional.
Sakal Papers (P) Ltd. v. The Union of India एक 1962 का संविधान पीठ का मामला था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि Newspaper (Price and Page) Act, 1956 और Daily Newspapers (Price and Page) Order, 1960 असंवैधानिक थे।
- The Sakal Papers case challenged the Newspaper (Price and Page) Act, 1956, which regulated the number of pages and pricing of newspapers.
Sakal Papers के मामले में Newspaper (Price and Page) Act, 1956 को चुनौती दी गई थी, जो समाचारपत्रों के पृष्ठों की संख्या और मूल्य को नियंत्रित करता था।
- The Supreme Court struck down the Act, affirming that such regulations violated the freedom of the press.
सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम को रद्द कर दिया, यह मानते हुए कि इस प्रकार के नियम प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं।



Q.

Which publication was involved in the Brij Bhushan vs. State of Delhi case?

बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य मामले में कौन-सा प्रकाशन शामिल था?

A

Crossroads

B

Organizer

C

Pratap

D

Indian Express



Explanation / व्याख्या

- The case involved the publication "**Organizer**," run by the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).
- The case challenged the pre-censorship order imposed on this publication.

- इस मामले में प्रकाशन "**Organizer**," जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) द्वारा चलाया जाता है, शामिल था।
- इस मामले में इस प्रकाशन पर लगाए गए पूर्व-सेंसरशिप आदेश को चुनौती दी गई थी।



UGC-NET PYQ's



Which section of the Information Technology Act was struck down in the Shreya Singhal vs. Union of India case?

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा को असंवैधानिक घोषित किया गया था?



(A)

Section 66B

(B)

Section 66A

(C)

Section 66E

(D)

Section 66C

Explanation / व्याख्या

- The Shreya Singhal vs. Union of India case challenged the constitutionality of Section 66A of the Information Technology Act, 2000.
- The Supreme Court struck down Section 66A, ruling that it was vague and overbroad, leading to arbitrary enforcement and a chilling effect on free speech.
- श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया, यह निर्णय देते हुए कि यह अस्पष्ट और व्यापक थी, जिससे मनमाने ढंग से लागू करने की प्रवृत्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दमनकारी प्रभाव पड़ता था।





Q.

The Supreme Court judgment in Broadcasting Corporation of India vs. Cricket Association of Bengal emphasized that airwaves are:

प्रसारण निगम ऑफ इंडिया बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि एयरवेव्स हैं:

A

Private property
निजी संपत्ति

B

State property
राज्य संपत्ति

C

Public property
सार्वजनिक संपत्ति



D

Corporate property
कॉरपोरेट संपत्ति



Answer / उत्तर: Option C / विकल्प C

Public property
सार्वजनिक संपत्ति



Explanation / व्याख्या

- In the case of Broadcasting Corporation of India vs. Cricket Association of Bengal, the Supreme Court of India ruled that airwaves are public property.
प्रसारण निगम ऑफ इंडिया बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एयरवेव्स सार्वजनिक संपत्ति हैं।
- This significant judgment ended the government monopoly over broadcasting and allowed private players to operate in this domain.
यह महत्वपूर्ण निर्णय प्रसारण पर सरकारी एकाधिकार को समाप्त करता है और निजी खिलाड़ियों को इस क्षेत्र में काम करने की अनुमति देता है।

Q. Match the case with its corresponding judgment:
निम्नलिखित मामलों को उनके संबंधित निर्णय से मिलाइए:

Cases / मामले

A) Indian Express Newspapers vs. Union of India

B) Shreya Singhal vs. Union of India

C) Broadcasting Corporation of India vs. Cricket Association of Bengal

D) Sakal Papers vs. Union of India

Judgments / निर्णय

i) Declared Section 66A of IT Act as unconstitutional

ii) Ended government monopoly over broadcasting

iii) Held import duties on newsprint unconstitutional

iv) Struck down Newspaper (Price and Page) Act, 1956

Options / विकल्प:

1. A3, B4, C1, D2

2. A3, B1, C2, D4

3. A2, B1, C3, D4

4. A1, B3, C4, D2



Explanation / व्याख्या

- **Indian Express Newspapers vs. Union of India:** The Supreme Court held that the imposition of import duties on newsprint was unconstitutional
- **Shreya Singhal vs. Union of India:** The Court declared Section 66A of the Information Technology Act as unconstitutional .
- **Broadcasting Corporation of India vs. Cricket Association of Bengal:** The judgment ended the government monopoly over broadcasting.
- **Sakal Papers vs. Union of India:** The Court struck down the Newspaper (Price and Page) Act, 1956 .
- **Indian Express Newspapers vs. Union of India:** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि समाचार पत्र के कागज़ पर आयात शुल्क लगाना असंवैधानिक था।
- **Shreya Singhal vs. Union of India:** न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया।
- **Broadcasting Corporation of India vs. Cricket Association of Bengal:** निर्णय में सरकारी एकाधिकार को समाप्त कर प्रसारण के क्षेत्र को स्वतंत्र किया गया।
- **Sakal Papers vs. Union of India:** न्यायालय ने समाचार पत्र (मूल्य एवं पृष्ठ) अधिनियम, 1956 को निरस्त कर दिया।





In Virendra Vs. State of Punjab, Section (3)(1) of the Punjab Special Powers (Press) Act, 1956, was struck down on the grounds of

विरेन्द्र बनाम पंजाब राज्य में, पंजाब विशेष शक्तियाँ (प्रेस) अधिनियम, 1956 की धारा (3)(1) को निम्नलिखित किस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया था?



(A) Procedural unreasonableness

(B) Public interest

(C) Over-regulation

(D) Political ill-will

Explanation / व्याख्या

- In Virendra Vs. State of Punjab, Section (3)(1) of the Punjab Special Powers (Press) Act, 1956, was struck down on the grounds of Procedural unreasonableness.
- Virendra, the petitioner the editor, printer, and publisher of the daily Pratap and Vir Arjun
- The Daily Pratap is a daily newspaper printed in the Urdu language and script, and it was started about 38 years ago in Lahore, the capital of the united Punjab.

- विरेन्द्र बनाम पंजाब राज्य में, पंजाब विशेष शक्तियाँ (प्रेस) अधिनियम, 1956 की धारा (3)(1) को निम्नलिखित आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया था: प्रक्रियात्मक असंगतता।
- विरेन्द्र, दैनिक प्रताप और वीर अर्जुन के संपादक, मुद्रक और प्रकाशक थे।
- दैनिक प्रताप एक उर्दू भाषा और लिपि का दैनिक समाचारपत्र है, और यह लगभग 38 वर्ष पूर्व लाहौर में, जो संयुक्त पंजाब की राजधानी थी, वहाँ प्रारंभ किया गया था।





Q.

The doctrine of direct impact was applied by the Supreme Court of India in the case of:

प्रत्यक्ष प्रभाव के सिद्धांत का उपयोग भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस मामले में किया गया?

1

Virendra Vs State of Punjab
वीरेंद्र बनाम पंजाब राज्य

2

Narendra Vs Union of India
नरेंद्र बनाम भारत संघ

3

Maneka Gandhi Vs. Union of India
मनेका गांधी बनाम भारत संघ



4

Babulal Vs State of Maharashtra
बबूलाल बनाम महाराष्ट्र राज्य



Answer / उत्तर: Option 3 / विकल्प 3

Maneka Gandhi Vs. Union of India

मनेका गांधी बनाम भारत संघ



Explanation / व्याख्या

- In the landmark case of Maneka Gandhi vs. Union of India (1978), the issue arose when the government of India impounded Maneka Gandhi's passport under the Passport Act of 1967, citing "public interest" as the reason, without giving a detailed explanation.
मनेका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले में, भारत सरकार ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत मनेका गांधी का पासपोर्ट "सार्वजनिक हित" का हवाला देते हुए, विस्तृत कारण बताए बिना जब्त कर लिया था।
- Maneka Gandhi challenged the constitutionality of the act, arguing that her passport was seized without a fair procedure and that this action violated her right to personal liberty under Article 21 of the Indian Constitution.
मनेका गांधी ने अधिनियम की संविधाननिकता को चुनोती दी, यह तर्क देते हुए कि उनका पासपोर्ट उचित प्रक्रिया के बिना जब्त किया गया और यह कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।
- The Supreme Court of India ruled in her favour.
सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय दिया।
- It expanded the interpretation of Article 21 to include the right to travel abroad and insisted that any law depriving a person of personal liberty must not only be procedurally but also substantively fair, just, and reasonable.
इसने अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार करते हुए विदेश यात्रा के अधिकार को भी शामिल किया और कहा कि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने वाला कोई भी कानून केवल प्रक्रियात्मक रूप से ही नहीं बल्कि सार्थक रूप से भी न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत होना चाहिए।
- This case fundamentally changed the way fundamental rights, particularly the right to life and personal liberty, were viewed and enforced in India.
इस मामले ने भारत में मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की दृष्टि और प्रवर्तन के तरीके को मूलभूत रूप से बदल दिया।



Q.

Match the following:

निम्नलिखित का मिलान कीजिए:

(Newspaper Case) / (समाचार पत्र मामले)

(Issues/act) / (मुद्दे/अधिनियम)

(Newspaper Case) / (समाचार पत्र मामले)	(Issues/act) / (मुद्दे/अधिनियम)
(a) Express newspapers	(i) Newspaper (Price and Page) Act, 1956
(b) Sakal newspaper	(ii) Breach of legislative privilege
(c) Bennett and Colema	(iii) Imposition of tax to limit circulation
(d) Searchlight newspaper	(iv) Newsprint Control Order, 1962

Codes: (a), (b), (c), (d)

1. (iii), (i), (iv), (ii)

2. (iv), (ii), (i), (iii)

3. (i), (ii), (iii), (iv)

4. (ii), (i), (iv), (iii)



Explanation / व्याख्या



(a) Express newspapers → (iii) Imposition of tax to limit circulation

(a) एक्सप्रेस समाचार पत्र → (iii) प्रसार को सीमित करने के लिए कर लगाया गया



(b) Sakal newspaper → (i) Newspaper (Price and Page) Act, 1956

(b) सकाल समाचार पत्र → (i) समाचार पत्र (मूल्य एवं पृष्ठ) अधिनियम, 1956



(c) Bennett and Colema → (iv) Newsprint Control Order, 1962

(c) बेनेट और कोलेमा → (iv) न्यूज़प्रिंट नियंत्रण आदेश, 1962



(d) Searchlight newspaper → (ii) Breach of legislative privilege

(d) सर्चलाइट समाचार पत्र → (ii) विधायी विशेषाधिकार का उल्लंघन



Correct Answer / सही उत्तर:

1. (iii), (i), (iv), (ii)





Assertion (A): In *Virendes V. State of Punjab*, Section 3 (1) of the Punjab Special Powers (Press) Act, 1956, was struck down by the Supreme Court as unreasonable.

Reason (R): It was not only on the grounds of substantive unreasonableness but also on the grounds of procedural unreasonableness.

अभिकथन (A): वीरेंद्रस वि. पंजाब राज्य में, पंजाब विशेष शक्तियाँ (प्रेस) अधिनियम, 1956 की धारा 3 (1) को सर्वोच्च न्यायालय ने अविवेकपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया था।

कारण (R): यह केवल ठोस अविवेकशीलता के आधार पर ही नहीं, बल्कि प्रक्रियात्मक अविवेकशीलता के आधार पर भी था।



(A)

Both (A) and (R) are true.

(B)

Both (A) and (R) are true, but (R) the correct explanation of (A).

(C)

(A) is true, but (R) is false

(D)

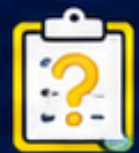
(A) is false, but (R) is true.

Explanation / व्याख्या

- The case *Virendra vs. State of Punjab* involved a legal challenge against the Punjab Special Powers (Press) Act of 1956.
- This Act allowed the government to impose pre-censorship on newspapers, meaning it could review and potentially block the publication of news before it was made public.
- This was seen as a way to prevent the press from publishing content that could be considered objectionable by the government.
- Government agreed with the plaintiff *Virendra* that these restrictions were unreasonable

- वीरेंद्र बनाम पंजाब राज्य का मामला पंजाब विशेष शक्तियाँ (प्रेस) अधिनियम, 1956 के खिलाफ एक कानूनी चुनौती थी।
- इस अधिनियम ने सरकार को समाचार पत्रों पर पूर्व-सेंसरशिप लगाने की अनुमति दी, जिसका अर्थ था कि वह सांख्यिक होने से पहले समाचारों की समीक्षा कर सकती थी और संभावित रूप से उसे रोक सकती थी।
- इसे प्रेस को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने से रोकने के तरीके के रूप में देखा गया जो सरकार द्वारा आपत्तिजनक मानी जा सकती थी।
- सरकार ने वादी वीरेंद्र से सहमति व्यक्त की कि ये प्रतिबंध अविवेकपूर्ण थे।





Q.

In the case of Ministry of Information and Broadcasting Vs. Cricket Association of Bengal, the Supreme Court judgement led to :

Ministry of Information and Broadcasting Vs. Cricket Association of Bengal के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने किस परिणाम को जन्म दिया?

A

censorship of foreign journals
विदेशी पत्रिकाओं पर सेंसरशिप

B

freeing electronic media from government monopoly
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सरकारी एकाधिकार से मुक्त करना



C

imposition of surcharge on media advertisements
मीडिया विज्ञापनों पर अधिभार लगाना

D

restriction of media coverage of cricket matches
क्रिकेट मैचों की मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध



Answer / उत्तर: Option 2 / विकल्प 2

freeing electronic media from government monopoly
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सरकारी एकाधिकार से मुक्त करना



Explanation / व्याख्या

- Ministry of Information and Broadcasting vs. Cricket Association of Bengal (1995) was about who has the right to broadcast sports events in India. Ministry of Information and Broadcasting vs. Cricket Association of Bengal (1995) का मामला भारत में खेल आयोजनों के प्रसारण के अधिकार को लेकर था।
- The Cricket Association of Bengal wanted to hire foreign broadcasters to telecast a cricket series in India, but the government-run Doordarshan argued that it had exclusive rights to broadcast cricket in India because it controlled the airwaves. Cricket Association of Bengal ने भारत में एक क्रिकेट श्रृंखला के प्रसारण के लिए विदेशी प्रसारकों को नियुक्त करना चाहा, लेकिन सरकारी दूरदर्शन ने दावा किया कि क्योंकि वह तरंगों (airwaves) को नियंत्रित करता है, इसलिए उसे भारत में क्रिकेट प्रसारण के विशेष अधिकार प्राप्त हैं।
- The Supreme Court of India heard the case and made a crucial decision in 1995. सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई की और 1995 में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया।
- The court ruled that airwaves, or frequencies used for broadcasting, are public property. न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रसारण के लिए उपयोग की जाने वाली तरंगें या आवृत्तियाँ सार्वजनिक संपत्ति हैं।
- This means that they belong to the people of India and not exclusively to the government or any single entity. इसका अर्थ है कि ये भारत के लोगों की हैं और न कि केवल सरकार या किसी एक इकाई की।



Q.

Bennet, Coleman & Co Vs. Union of India case in early 1970s deals with

बेनेट, कोलमन एंड कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला (प्रारंभिक 1970 के दशक) किससे संबंधित है?

- A Pre-censorship
- B Journalist wages
- C Editorial perspective
- D Newsprint policy**



Explanation / व्याख्या

Bennett Coleman & Co. vs Union of India (1972)

- In this landmark case, the Supreme Court invalidated certain government policies that placed restrictions on the import of newsprint and allocation, which directly affected the publication capabilities of newspapers, including The Times of India.
- The Supreme court held that these restrictions were a violation of the freedom of the press.

- इस ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उन कुछ सरकारी नीतियों को अमान्य कर दिया, जिन्होंने समाचारपत्र के आयात और आवंटन पर प्रतिबंध लगाए थे, जिससे द दायम्स ऑफ इंडिया सहित समाचारपत्रों की प्रकाशन क्षमताएं सीधे प्रभावित हुईं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये प्रतिबंध प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन थे।



Q.

The first amendment to Article 19(1) (a) of the Indian Constitution was mainly aimed to include _____ as a cause for reasonable restriction.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के प्रथम संशोधन का मुख्य उद्देश्य युक्तिसंगत प्रतिबंध के आधार के रूप में _____ को शामिल करना था।

A

Public order
सार्वजनिक व्यवस्था

**B**

Censorship
सेंसरशिप

C

Newspaper registration
समाचार पत्र पंजीकरण

D

Licensing printing press
मुद्रणालय लाइसेंसिंग



Answer / उत्तर: Option A / विकल्प A
Public order
सार्वजनिक व्यवस्था

**Explanation / व्याख्या**

- The First Amendment to the Constitution, made in 1951, introduced "**public order**" as a ground on which the state can place reasonable restrictions on this right.
संविधान के प्रथम संशोधन, जो 1951 में किया गया था, ने "सार्वजनिक व्यवस्था" को एक ऐसे आधार के रूप में शामिल किया, जिस पर राज्य इस अधिकार पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगा सकता है।
- The intention behind this amendment was to address the need for maintaining stability and order within the society, which can sometimes be disrupted by unrestricted exercise of free speech.
इस संशोधन का उद्देश्य समाज में स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता को संबोधित करना था, जिसे मुक्त भाषण के अनियंत्रित प्रयोग से कभी-कभी विचलित किया जा सकता है।



One landmark case related to the first amendment of the Indian Constitution, particularly Article 19(1)(a), is "Romesh Thappar vs. The State of Madras" (1950).

UGC-NET PYQ's



The Newspaper (price and Page) Act, of 1956, was challenged in the Supreme Court by



समाचारपत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम, 1956 को सर्वोच्च न्यायालय में किसके द्वारा चुनौती दी गई थी?

(A)

The pioneer

(B)

Sakal

(C)

Gujarat Samachar

(D)

The Thanthi

Explanation / व्याख्या

- The Newspaper (Price and Page) Act of 1956 was challenged in the Supreme Court by Sakal Papers (P) Ltd. v. The Union of India in 1962.
- The case was filed by the newspaper's proprietor, shareholders, and two readers, who claimed that the act violated their right to free speech.
- The act gives the central government the power to regulate the price of newspapers based on their page count and the amount of space allocated for advertising. The court struck down Section 3(1) of the act.

- समाचारपत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम, 1956 को सर्वोच्च न्यायालय में Sakal Papers (P) Ltd. v. The Union of India द्वारा 1962 में चुनौती दी गई थी।
- यह मामला समाचारपत्र के स्वामी, शेयरधारकों और दो पाठकों द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने दावा किया कि यह अधिनियम उनके मुक्त भाषण के अधिकार का उल्लंघन करता है।
- यह अधिनियम केंद्र सरकार को पृष्ठ संख्या और विज्ञापन के लिए आवंटित स्थान की मात्रा के आधार पर समाचारपत्रों के मूल्य को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। न्यायालय ने अधिनियम की धारा 3(1) को निरस्त कर दिया।



Q.

The applicability of Article 14 of the Indian Constitution was invoked by the Supreme Court in the case involving the newspaper :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की प्रयोज्यता का उल्लेख उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया जिसमें निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध था?



A

Sakal / सकल

B

Aajkal / आजकल

C

The Hindustan Times / द हिंदुस्तान टाइम्स

D

The Times of India / द टाइम्स ऑफ इंडिया

Explanation / व्याख्या



- Sakal Newspapers Ltd. vs. The Union of India (1962) was a significant case in the context of Article 14, which pertains to the right to equality before the law. / सकल न्यूजपेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1962) अनुच्छेद 14 के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मामला था, जो कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है।
- Sakal Newspapers challenged the constitutionality of the Newspaper (Price and Page) Act, 1956, which sought to regulate the number of pages a newspaper could publish about its price. / सकल न्यूजपेपर्स ने समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम, 1956 की संबैधानिकता को चुनौती दी, जो समाचार पत्र द्वारा अपने मूल्य के बारे में प्रकाशित किए जाने वाले पृष्ठों की संख्या को नियंत्रित करना चाहता था।
- The Supreme Court held that this Act violated the newspaper's right to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) and was not a reasonable restriction under Article 19(2). / सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह अधिनियम अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत समाचार पत्र के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है और अनुच्छेद 19(2) के तहत एक उचित प्रतिबंध नहीं था।
- The Court also invoked Article 14, asserting that the Act created an unreasonable classification between newspapers, thus violating the right to equality. / न्यायालय ने अनुच्छेद 14 का भी उल्लेख किया, यह कहते हुए कि अधिनियम ने समाचार पत्रों के बीच एक अवैध वर्गीकरण किया, इस प्रकार समानता के अधिकार का उल्लंघन किया।